जंतर-मंतर 2.0 का महासंग्राम! हिरासत, बैरिकेडिंग और मानवाधिकारों पर महासवाल! दुनियाँ की नज़रें भारत पर टिक गईं?



वैश्विक स्तरपर दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की बहस के केंद्र में है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और चुनावी सुधारों की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को कॉलरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया,जो अब सुप्रीम कोर्ट की 11अक्टूबर 2026 को विशेष रविवार सुनवाई और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की चिंता तक पहुंच गया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी को अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए खारिज किया है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि अब यह केवल एक प्रदर्शन की अनुमति का विवाद नहीं रह गया है।इसके केंद्र में पांच बड़े सवाल हैं,क्या शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को पर्याप्त संरक्षण मिला, क्या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक थे, क्या सार्वजनिक परिवहन और इंटरनेट सेवाओं को प्रभावित करना ज़रूरी था,क्या हिरासत की प्रक्रिया कानूनके अनुरूप रही और क्या चुनावी संस्थाओं पर उठ रहे सवालों का जवाब सटीकता से संवाद से दिया जाएगा या टकराव से?

साथियों बात अगर हम जंतर-मंतर 1.0 से 2.0 तक- शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब चुनाव प्रमुख पर निशाना इसको समझने की करें तो, इस आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि समझना ज़रूरी है।उपलब्ध समाचारों के अनुसार सीजेपी ने पहले भी युवाओं के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए थे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक ताकत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।अब 10 अक्टूबर के प्रदर्शन का केंद्र मुख्य निर्वाचन का इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की जांच है।आंदोलनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटने से चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।दूसरी ओर,निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज किया है।इसलिए इन दावों को सिद्ध तथ्य नहीं, बल्कि जांच और जवाबदेही की मांग से जुड़े आरोपों के रूप में देखना चाहिए।युवाओं के इस आंदोलन को जंतर-मंतर 2.0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह केवल किसी एक मंत्री या अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं,बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे से जुड़ी बहस बन गया है।हालांकि,यह कहना कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से डर गई है, अभी उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता।इतना ज़रूर है कि व्यापक सुरक्षा प्रबंध,नेताओं की हिरासत, परिवहन प्रतिबंध और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई ने विवाद को राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा तक पहुंचा दिया।

साथियों बात अगर हम प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली? सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकार को समझने की करें तो, दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार,आयोजकों ने 7 अक्टूबर को सूचना दी थी,जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत कम-से-कम दस दिन पहले आवेदन अपेक्षित होता है। पुलिस ने पिछले प्रदर्शनों में नियमों और लिखित आश्वासनों के कथित उल्लंघन, यातायात संबंधी कठिनाइयों तथा कानून- व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा की आशंकाओं का भी हवाला दिया।केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी जोखिमों को लेकर सतर्कता बरतने की बात सामने आई।यहां संवैधानिक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं; सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि अनुमति न मिलने पर प्रशासन को हर परिस्थिति में असीमित कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है।प्रतिबंधों की आवश्यकता, अवधि भौगोलिक सीमा और अनुपात की समीक्षा न्यायिक कसौटी पर की जा सकती है।दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू होने की बात भी सामने आई। यह धारा तत्काल रोकथाम और संभावित खतरे से बचाव के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान देती है। किंतु इसका प्रयोग भी कानून के अनुसार होना चाहिए। इसी बिंदु पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध,नेताओं की हिरासत, परिवहन प्रतिबंध और प्रशासन की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी आमने- सामने दिखाई दी। साथियों बात अगर हम हजारों हिरासतों का विवाद, मेट्रो बंदी और सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझने की करें तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों में दो हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने का उल्लेख है;कुछ रिपोर्टों में इससे अधिक आंकड़े भी सामने आए। सीजेपी के संस्थापक तथा सह-संयोजक और एक अन्य को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिए जाने की खबर आई। एक यूट्यूबर और विपक्षी नेताओं सहित अन्य लोगों की हिरासत का मामला भी चर्चा में रहा।अलग-अलग रिपोर्टों में संख्या और हिरासत की परिस्थितियों के विवरण एक समान नहीं हैं,इसलिए किसी एक अपुष्ट आंकड़े को अंतिम सरकारी संख्या मानना उचित नहीं होगा। विवाद केवल हिरासत तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश प्रतिबंधित किए गए और रेल सेवाओं में व्यवधान की खबरें आईं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में दावा किया कि लोगों को प्रदर्शन स्थल से दूर क्षेत्रों और ट्रेनों से भी हिरासत में लिया गया, इंटरनेट सेवाएं बाधित हुईं और वकीलों, महिलाओं,छात्रों तथापत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये आरोप सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए थे; इन्हें सभी मामलों में न्यायिक रूप से सिद्ध निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ही सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित संचालन और आम जनता की सुविधा का ध्यान रखने पर जोर दिया था।11 अक्टूबर को रविवार होने के बावजूद न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी.मोहना की विशेष पीठ ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस असाधारण सुनवाई ने सटीकता से विवाद को नया मोड़ दिया।

साथियों बात अगर हम रविवार को सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई- सरकार और प्रशासन को कड़े संदेश को समझने की करें तो 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दो प्रमुख प्रकार की याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं।पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की स्थिति और हिरासत की वैधता पर सवाल उठाए गए।वरिष्ठ अधिवक्ता ने विपक्षी नेताओं की एहतियाती हिरासत को चुनौती दी। दूसरी,अवमानना याचिका, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों नेसार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने संबंधी 9 अक्टूबर के न्यायालयीन निर्देशों का पालन नहीं किया। एक अधिवक्ता की याचिका इसी विवाद से संबंधित थी। सुनवाई के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों ने हिरासत, बैरिकेडिंग, मेट्रो बंदी और वकीलों की न्याय तक पहुंच बाधित होने के आरोप उठाए।अदालत के सामने पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार को लेकर भी दलीलें रखी गईं।इन दावों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष और न्यायिक जांच महत्वपूर्ण होगी।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो सेवाएं सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलाने,इंटरनेट सेवाओं को कानून के विपरीत बाधित न करने,बैरिकेडिंग की समीक्षा करने और बिना वैधानिक प्रक्रिया किसी को हिरासत में नहीं लेने पर जोर दिया।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 163 के आदेश से प्रभावित क्षेत्र के बाहर लोगों की आवाजाही और शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार को अनावश्यक रूपसे नहीं रोका जाना चाहिए।न्यायालय परिसर के बाहर धारा 163 का उल्लेख करने वाला बोर्ड हटाने का निर्देश भी दिया गया, ताकि न्याय तक पहुंच बाधित न हो। संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

साथियों बात अगर हम तीन आंदोलन कर्ताओं के रहा होने और सीजेपी प्रमुख की दादी के निधन पर क्या हुआ? इसको समझने की करें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावनात्मक प्रसंग सीजेपी संस्थापक की दादी के निधन का रहा। समाचारों के अनुसार,उनकी 85 वर्षीय दादी का महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में निधन हुआ था। तथा वे दिल्ली में हिरासत में थे,जिसके कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने को लेकर सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनको निधन की जानकारी संवेदनशीलता के साथ दी गई थी और अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह नगर जाने में मानवीय आधार पर सहायता की पेशकश की गई थी।दूसरी ओर सीजेपी और उनके परिवार से जुड़े लोगों ने सूचना और संपर्क को लेकर सवाल उठाए। इस प्रकार पुलिस का पक्ष और परिवार की आपत्ति अलग- अलग सामने आई;दोनों को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण है।11अक्टूबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद,सीजेपी प्रमुख व अन्य दो को रिहा कर दिया गया।रिपोर्टों के मुताबिक,रिहाई की शर्त एक वर्ष तक शांति बनाए रखने से संबंधित थी।

साथियों बात अगर हम संयुक्त राष्ट्र पहुंचा मामला- मानवा धिकार कार्यालय ने क्या कहा? इसको समझने की करें तो,दिल्ली की कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने विवाद को और व्यापक बनाया।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) के प्रवक्ता थमीम अल-खीथान ने प्रदर्शनकारियों, आंदोलन के नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर चिंता व्यक्त की। कार्यालय ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने, कानून लागू करने वाले कर्मियों से अत्यधिक संयम बरतने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल तथा बिना शर्त रिहा करने का आग्रह किया। उसने चिंताओं के समाधान के लिए सार्थक संवाद की जरूरत भी बताई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी मानवाधिकार संबंधी चिंता और अपील थी; इसे भारत के विरुद्ध किसी न्यायिक फैसले या औपचारिक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की टिप्पणियां सरकारों की कार्रवाई, नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक मानकों पर सार्वजनिक बहस को सटीकता से प्रभावित कर सकती हैं।

साथियों बात अगर हम भारत का पलटवार-हमारे आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप न करें इसको समझने की करें तो संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी के जवाब में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने 10 अक्टूबर की देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ा वक्तव्य दिया। भारत ने ओएचसीएचआर की चिंताओं को गलत संदर्भ पर आधारित और देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया।भारत का तर्क था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया से संरक्षित है। साथ ही, भारत ने कहा कि हर लोकतंत्र की तरह यहां भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध लागू होते हैं, अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और शिकायतों के निवारण के लिए अदालतें उपलब्ध हैं।भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से निष्पक्षता तथा गैर-चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने और दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों पर भी समान ध्यान देने की अपेक्षा जताई। इस प्रकार विवाद अब केवल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन की बहस बन गया।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि असली परीक्षा सत्ता की ताकत की नहीं, लोकतंत्र के संतुलन की है।जंतर -मंतर 2.0 ने भारत के सामने एक असहज लेकिनजरूरी सवाल खड़ा किया है,लोकतंत्र में असहमति को किस तरह संभाला जाना चाहिए?हमेशा प्रशासन का दायित्व

सार्वजनिक सुरक्षा यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।दूसरी ओर,नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध, अपनी बात रखने और न्यायालय तक पहुंचने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।किसी भी पक्ष की कार्रवाई को इन दोनों जिम्मेदारियों की कसौटी पर परखना होगा।अब असली कसौटी यह होगी कि क्या सरकार, पुलिस और प्रदर्शनकारी संवाद का रास्ता अपनाते हैं; क्या चुनावी अनियमितताओं के आरोपों पर तथ्यपरक जवाब सामने आते हैं; और क्या अदालत की निगरानी में नागरिक अधिकारों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि विरोध की आवाज कितनी आसानी से रोकी जा सकती है, बल्कि इससे मापी जाती है कि संस्थाएं उस आवाज का जवाब कितनी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ देती हैं।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया
महाराष्ट्र 9226229318

विचारों की नई दिशा और बेहतर समाज के संकल्प के साथ कार्यक्रम 'विचार तरंग' का आयोजन

बदलते परिवेश में नैतिक शिक्षा

बेंगलुरु। जिया माँ साहित्य मंच एवं श्रीम न्यूज नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में साहित्य, समाज और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय बदलते परिवेश में नैतिक शिक्षा पर एक विशेष कार्यक्रम 'विचार तरंग' का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को किया गया 7

इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अनुभवी एवं प्रतिष्ठित गुणीजनों ने अपने विचार साझा किये । कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक परिवेश में आवश्यक सकारात्मक चिंतन को बढ़ावा देना तथा समाज के बेहतर भविष्य के लिए विचारों का आदान-प्रदान करना था ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद एवं अनुवादक डॉ. मैथिली पी. राव ने की , जबकि सीएमएस बिज़नेस स्कूल, जैन (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी), बेंगलुरु में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में पीएचडी स्कॉलर ब्रिगेडियर डी.के. अचल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। क्राइस्ट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के भाषा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सेतु कुमार वर्मा , वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. उर्मिला पोरवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई । कार्यक्रम में नई पीढ़ी के विचारों और दृष्टिकोण को



जानने के लिए क्राइस्ट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के छात्र एडम सैम मैथ्यू की सहभागिता भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही 7

डॉ मैथिली पी राव ने अपने व्याख्यान में कहा कि नैतिकता समय उम्र और परिवेश के साथ बदलती है । नैतिकता का विषय एक व्यक्ति से होकर एक समाज ,एक राष्ट्र और फिर विश्व की ओर जाता है ।

ब्रिगेडियर डी.के. अचल ने कहा कि चरित्र कोई दार्शनिक निबंध नहीं है जिसे आप एक वातानुकूलित वातावरण में लिखते हैं। चरित्र वो है जब आप अपने पड़ोसी के कष्ट के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं।

डॉ सेतु वर्मा ने अपने व्याख्यान में कहा कि जो हम बचपन में सीखते हैं वह हमें आजीवन याद रहता है । छोटी उम्र में बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान उनके परिवार से ही मिलता है । बच्चों को नैतिकता सिखाने में परिवार का बड़ा योगदान होता है।

डॉ. उर्मिला पोरवाल ने बताया कि नैतिक शिक्षा सिर्फ हमें पढ़ना लिखना नहीं सिखाती बल्कि हमें आदर्शों का पालन करना सिखाती है । प्राचीन गुरु कुलों की बात करें तो वहां भी शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है ।

एडम सैम मैथ्यू ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ हमें नैतिकता की राह पर भी शिखर पर जाना है ।

रीता सिंह ने कहा कि कभी बच्चे दादा-दादी की कहानियों से जीवन के संस्कार सीखते थे।

आज उसी बच्चे के हाथ में किताब के साथ मोबाइल है,और शिक्षक के साथ अनेक डिजिटल माध्यम भी हैं। लेकिन प्रश्न यह है– क्या हमारे मूल्य भी बदल गए हैं?

रीता सिंह द्वारा कार्यक्रम का संचालन, धन्यवाद ज्ञापन किया गया । एडन सैम मैथ्यू द्वारा राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ ।

कार्यक्रम में मंच के सह संस्थापक लेफ्टिनेंट किशोर सिंह राठौर एवं श्रीयम न्यूज नेटवर्क के संपादक टी सी विश्वकर्मा जी भी उपस्थित रहे । कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिया मां साहित्य मंच के यू ट्यूब चैनल पर हुआ ।



बाल साहित्य में डॉ. सत्यवान सौरभ का परचम, 'प्रज्ञान' को मिला 31 हजार रुपये का श्रेष्ठ कृति पुरस्कार

मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का श्रेष्ठ कृति सम्मान, पीएच.डी. साहित्यकार दंपती डॉ. सत्यवान सौरभ व डॉ. प्रियंका सौरभ की 27 पुस्तकों के साहित्यिक सफर में जुड़ी नई उपलब्धि; बेटे प्रज्ञान के नाम पर लिखी पुस्तक दुनिया के सभी बच्चों को समर्पित

हिसार। साहित्यकार एवं लेखक डॉ. सत्यवान सौरभ की बाल साहित्य कृति 'प्रज्ञान' को हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2023 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अकादमी द्वारा घोषित परिणामों में 'प्रज्ञान' का चयन बाल साहित्य वर्ग में किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत चयनित कृति को 31 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने हिंदी, हरियाणवी, संस्कृत एवं पंजाबी सहित विभिन्न भाषाओं में प्राप्त साहित्यिक कृतियों के लिए वर्ष 2023 के परिणाम घोषित किए हैं। अकादमी की श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना के अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक विधाओं में श्रेष्ठ रचनाओं का चयन किया गया है। इसी क्रम में हिसार में रह रहे बड़वा (भिवानी) के डॉ. सत्यवान सौरभ की 'प्रज्ञान' को बाल साहित्य वर्ग में सम्मान के लिए चुना गया है।

'प्रज्ञान' डॉ. सत्यवान सौरभ की बाल साहित्य पर केंद्रित कृति है, जिसमें बच्चों के लिए साहित्यिक, संस्कारपरक एवं विचारपरक सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक की विशेष बात यह है कि लेखक ने इसे अपने बेटे प्रज्ञान के जन्म के अवसर पर दुनिया के सभी बच्चों को समर्पित किया है। पुस्तक के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशक्ति, संवेदनशीलता, संस्कार और रचनात्मक सोच को साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

डॉ. सौरभ लंबे समय से लेखन, पत्रकारिता और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, समकालीन विषयों तथा बाल साहित्य के प्रति विशेष रुचि दिखाई देती है। विभिन्न विधाओं में सक्रिय उनकी साहित्यिक यात्रा में 'प्रज्ञान' बाल साहित्य के प्रति उनके रचनात्मक सरोकार को सामने लाती है।

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री के अनुसार वर्ष 2023 की श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना के परिणामों को अकादमी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। बाल साहित्य वर्ग में डॉ. सत्यवान सौरभ की 'प्रज्ञान' का चयन इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है।

डॉ. सत्यवान सौरभ की साहित्यिक यात्रा में यह सम्मान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जुड़ा है। उनकी कृति को राज्य की साहित्यिक संस्था द्वारा बाल साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में स्थान मिलना बच्चों के लिए साहित्य लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान की संस्थागत मान्यता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "बाल साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के संस्कार, कल्पनाशक्ति, संवेदनशीलता और विचार-निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है।" बच्चों के लिए सार्थक और मूल्यपरक साहित्य का सृजन उनकी साहित्यिक प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।

डॉ. सत्यवान सौरभ की पत्नी डॉ. प्रियंका सौरभ भी चर्चित लेखिका एवं साहित्यकार हैं। दोनों ने राजनीतिक विज्ञान में पीएच.डी. की है और साहित्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए संयुक्त रूप से तथा स्वतंत्र रूप से अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। दोनों के लेखन में सामाजिक सरोकार, समकालीन विमर्श, महिला सशक्तीकरण, बाल साहित्य और सामाजिक चेतना जैसे विषय प्रमुखता से उभरते हैं। दोनों साहित्यकारों की अब तक 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा 'प्रज्ञान' को 31 हजार रुपये के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने से भिवानी के साहित्यिक क्षेत्र में भी प्रसन्नता का माहौल है। साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने डॉ. सत्यवान सौरभ को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे भिवानी के साहित्यिक परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।